allotting poromboke lands for raising private forests does not, therefore, arise.

(b) Afforestation of wastelands held by private persons is being encouraged through programmes of agro-forestry and farm-forestry.

Area of Dal Lake in Kashmir

202. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) what was the total area of Dal Lake in Kashmir in 1950;

(b) what is the areas at present; whether it has shrunk;

(c) whether the colour of water in Dal has changed; if so, the reasons therefor; and

(d) what steps are contemplated to set it right ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) and (b) As per available information, within the living memory, the open water area of the Dal Lake has shrunk from 24 sq. km. to 15 sq. km.

(c) and (d) In a small portion in South Eastern part of the Lake, the water colour has changed due to red scum like formation of algal bloom. The State Government of Jammu and Kashmir have sanctioned Rs. 2.00 lakhs so far to investigate the causative factors responsible for the algal bloom and the remedial measures to prevent its recurrence.

देश में जलाऊ लकड़ी की गुणवत्ता

203. श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वनों में जलाऊ लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ताकि उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके ;

(ख) लोगों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में जलाऊ लकड़ी इस्तेमाल की जा रही है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो, तो वैकल्पिक उपाय के लिये बतौर जलाऊ लकड़ी के वृक्ष लगाने की योजनाओं में किन-किन राज्यों में प्रगति हो रही है तथा यह कार्य कितने-कितने क्षेत्र में हो रहा है ; और

(घ) ऐसे वृक्षों के नाम क्या-क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1987 के अनुसार, देश में जलाने की लकड़ी की अनुमानित मांग लगभग 235 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि सतत वार्षिक अनुमानित वन उत्पादन लगभग 40 मिलियन घन मीटर है ।

(ग) "क्षेत्रोन्मुख जलाने की लकड़ी और चारा परियोजना" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है इस स्कीम के तहत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिये)

(घ) जलाने की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम के तहत निम्नलिखित मुख्य प्रजातियां उगाई जा रही हैं:—

1. अकेशिया निलोटिका
2. प्रोसोपिस जूलीफलोरा
3. अकेशिया आरिकुलिफार्मिस
4. कैजुअरिना इक्विपसिटीफोलिया
5. यूकेलिप्टस टेरिटिकोर्निस
6. केशिया सियामिया
7. पाइनस राक्सबर्घी
8. अकेशिया केटेचु
9. ल्यूकीना ल्यूकोसिफाल।
10. करकस प्रजातियां

विवरण

(क्षेत्र है० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990–91 तक
1.	आंध्र प्रदेश	6580
2.	अरूणाचल प्रदेश	370
3.	असम	4035
4.	बिहार	7014
5.	गोआ	210
6.	गुजरात	5000
7.	हरियाणा	7253
8.	हिमाचल प्रदेश	1237
9.	जम्मू व कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	1092
11.	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	5794
13.	महाराष्ट्र	—
14.	मणिपुर	4480
15.	मेघालय	1558
16.	मिजोरम	3000
17.	नागालैंड	—
18.	उड़ीसा	8245
19.	पंजाब	2250
20.	राजस्थान	9230
21.	सिक्किम	951
22.	तमिलनाडु	3102
23.	त्रिपुरा	1940
24.	उत्तर प्रदेश	7160
25.	पश्चिम बंगाल	4408
	कुल :	84909

बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समितियों का गठन

204. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वायु तथा जल के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिलास्तर पर समितियों का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसी कितनी समितियां बनाई गयी हैं; तथा उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन समितियों ने अभी तक सरकार को क्या-क्या सिफारिशें भेजी हैं ; और

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) रासायनिक दुर्घटनाओं के मामले में संकट प्रबन्ध के लिए सभी राज्यों में जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं । इन समितियों को निवारक उपाय करने होते हैं और दुर्घटना हो जाने पर संकट की